



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1993/माघ 15, 1914

No. 27] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1993/MAGHA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 101/(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1993

फाइल सं. 6/14/92-ई पी सी:—निर्यात आयात-निर्यात, 1992-97 के पैराग्राफ
16 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया
पुस्तक, 1992-97 में निम्नलिखित संशोधित करते हैं :—

1. अध्याय-15 के पैराग्राफ 233 में अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

“तथापि, निर्यात संबंधित पूंजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत संबंधित पूंजीगत माल के
अनुरक्षण के लिए अपेक्षित मानक अतिरिक्त पुर्जों का आयात पूंजीगत माल के बीमा

भाड़ा समस्त मूल्य के 10% तक किया जाएगा बशर्ते कि पूंजीगत माल के साथ प्रतिरिक्त पुर्जों का भी प्रेषित किया जाए। ऐसे प्रतिरिक्त पुर्जों का आयात नीति पुस्तक के पैराग्राफ 38 में निर्धारित निर्यात दायित्व के अन्वयेन किया जाएगा।

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

सी. के. मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 101(PN)/92—97

New Delhi, the 4th February, 1993

File No. 6/14/92-EPC(pt.)—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 1992-97 :—

1. In Chapter XV, paragraph No. 233, the following shall be added at the end :—

“However, under the Export Promotion Capital Goods Scheme, standard spare parts required for the maintenance of the concerned capital goods may be imported upto 10 per cent of the cif-value of the capital goods provided the spare parts are imported along with the capital goods. Such import of spare parts shall be subject to the export obligation as prescribed in paragraph 38 of the Policy Book”.

2. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade